



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]

नई दिल्ली, बुधस्पर्तिवार, सितम्बर 3, 2009/भाद्र 12, 1931

No. 285]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2009/BHADRA 12, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2009

विषय : जापान तथा थाइलैण्ड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

सं. 14/31/2009-डीजीएडी.- यतः, मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है) ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) एवं सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) के अनुसरण में जापान तथा थाइलैण्ड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है और संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्कों के अधिरोपण हेतु पाटनरोधी जांच शुरु करने का अनुरोध किया है । मै. एसआई ग्रुप-इंडिया लि. ने आवेदन का समर्थन किया है ।

2. और यतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन व क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है, अतः प्राधिकारी, कथित पाटन की मौजूदगी, सीमा तथा प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की वह राशि संस्तुत करने, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन की जांच एतद्वारा शुरु करते हैं ।

3. जाँच हेतु विचाराधीन उत्पाद एसीटोन है । इस उत्पाद का विपणन दो ग्रेडों अर्थात् क्रिस्टेलिन तथा हाइड्रेटेड में किया जाता है । दोनों ग्रेडों को एसीटोन की प्रवाहगत विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग किया जाता है । एसीटोन एक आधारभूत कार्बनिक रसायन है जिसे

डाइमिथाइल किटोन के नाम से भी जाना जाता है और जिसका रासायनिक सूत्र CH_3COCH_3 है। इस उत्पाद का विनिर्माण दो अलग-अलग प्रक्रियाओं अर्थात् क्यूमिनरूट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (आईपीए) आधारित रूट तथा इथेनॉल अल्कोहल आधारित रूट के जरिए किया जाता है। एसीटोन का उपयोग सॉल्वेंट या मध्यवर्ती के रूप में अनेक कार्बनिक सिंथेसिस में किया जाता है। इसका उपयोग बल्क भेषज, कृषि रसायन, रंजक पदार्थ, कुछेक विस्फोटक पदार्थ तथा अनुषंगी रसायनों के विनिर्माण में किया जाता है। एसीटोन का उपयोग आइसोफोरोन, डाई-एसीटोन, अल्कोहल, मिथाइल मेथाक्राइलेट तथा बिस्फेनोल-ए के विनिर्माण में किया जाता है। इसके अलावा, एसीटोन का उपयोग कुछेक रबड़ रसायनों, ऑक्सी एसीटीलिन, सेल्यूलोज एसिटेट के विनिर्माण में और रंगों/कोटिंग के विनिर्माण में विलायक के रूप में भी किया जाता है।

4. एसीटोन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के टैरिफ उप-शीर्ष सं. 2914.11 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग और उसका आधार

5. यह आवेदन मै. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लि. द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका मै. एसआई ग्रुप-इंडिया लि. ने समर्थन किया है। देश में संबद्ध वस्तु के केवल दो ज्ञात उत्पादक हैं। आवेदन में प्रदत्त सूचना के अनुसार हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लि. का उत्पादन अप्रैल, 08-सितम्बर, 08 के दौरान भारतीय उत्पादन का 50% और अक्टूबर, 08-मार्च, 09 के दौरान 55% बनता है और समर्थक के साथ उसका हिस्सा भारतीय उत्पादन का 100% बनता है। इस प्रकार आवेदक वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ “घरेलू उद्योग” होगा।

6. उपर्युक्त की जाँच के बाद प्राधिकारी यह निर्धारण करते हैं कि आवेदक, नियम 2 के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार आधार संबंधी मानदण्ड को पूरा करता है।

शामिल देश

7. वर्तमान जाँच में शामिल देश जापान और थाइलैण्ड हैं।

समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एसिटोन और संबद्ध देशों से निर्यातित एसिटोन में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा उत्पाद के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इनमें अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएँ हैं। आगे यह दावा किया गया है कि उपभोक्ताओं ने दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किया है। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के “घरेलू समान वस्तु” माना जा रहा है।

सामान्य मूल्य

9. थाइलैण्ड और जापान में घरेलू बिक्री के संबंध में आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव में आवेदक ने संबंध देशों में संबंध वस्तुओं की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए संरचित मूल्यों के आधार पर संबंध देशों में संबंध वस्तुओं के सामान्य मूल्य पर विचार किया है और इसमें थाइलैण्ड के संबंध में उच्चतर ब्याज लागत का समायोजन किया गया है और इस पर प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया है।

निर्यात कीमत

10. संबंध देशों से संबंध वस्तुओं की निर्यात कीमत का दावा इंटरनेशनल बिजनेस इन्फॉर्मेशन सर्विसेज (आईबीआईएस), मुंबई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है। समुद्री मालभाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय तथा अंतर्देशीय मालभाड़े आदि के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है और इसे उपयुक्त सीमा तक कम कर दिया गया है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा सामान्यतः किया जाता है। संबंध देशों से संबंध वस्तुओं के संबंध में आवेदक द्वारा दावा की गई निर्यात कीमतों का पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है।

पाटन मार्जिन

11. संबंध देशों के संबंध में कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत की तुलना की गई है, जो संबंध देशों के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है कि जापान और थाइलैण्ड में संबंध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जो प्रथम दृष्ट्या यह दर्शाता है कि संबंध देशों के निर्यातकों द्वारा संबंध वस्तुओं का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

12. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों से इतर कारकों के कारण नहीं हुई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

- (i) संबंध वस्तुओं का आयात मुख्यतः जापान, थाइलैण्ड और उन देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू है, से किया जा रहा है। अन्य देशों से किए गए आयात मामूली हैं।
- (ii) माँग में जहाँ जाँच अवधि के दौरान इसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट आई है, वहीं इसी अवधि के दौरान संबंध आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा माँग एवं उत्पादन के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- (iii) विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः इसका क्षति में कोई योगदान नहीं हो सकता।
- (iv) कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति भी नहीं है, जिसका घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान रहा हो।
- (v) संबंध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः यह क्षति का कारक नहीं है।
- (vi) संबंधित उत्पाद के संबंध में आवेदक की कोई उल्लेखनीय निर्यात गतिविधि नहीं है। अतः आवेदक के निर्यात कार्य निष्पादन से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

13. एक बार यदि यह सिद्ध कर दिया जाता है कि पाटित आयातों के कारण मात्रा एवं कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और पाटित आयातों द्वारा क्षति का प्रभाव सिद्ध कर दिया जाता है, तब असंबद्ध विश्लेषण, अर्थात् अन्य कारक जिनके कारण क्षति हुई है एकमात्र आधार है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है। चूँकि सूचीबद्ध ज्ञात कारकों से यह सिद्ध नहीं होता कि इनसे क्षति हुई है, अतः एकमात्र सुविचारित अभिमत यह है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देशों सहित अनेक स्रोतों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई है। उपर्युक्त मानदण्ड जहाँ यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति अन्य कारकों की वजह से नहीं हुई है, वहीं आवेदक ने यह निवेदन किया है कि निम्नलिखित मानदण्ड सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है :-

- क) संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी। इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई।
- ख) पाटित आयातों की मात्रा में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में गिरावट आई।
- ग) घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्राओं में आई गिरावट के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी गिरावट आई।
- घ) घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट की परिणति घरेलू उद्योग के लाभ एवं तत्पश्चात् नकद प्रवाह तथा लगाई गई पूँजी से आय में गिरावट के रूप में हुई।

14. इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को प्रथम दृष्ट्या वास्तविक क्षति हो रही है।

पाटनरोधी जाँच की शुरूआत

15. उपर्युक्त पैराग्राफ में किए गए विवेचन के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के अस्तित्व, सीमा तथा प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करते हैं।

जाँच अवधि (पी ओ आई)

16. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि 1 अक्टूबर, 2008 से 30 जून, 2008 (9 माह) है। तथापि क्षति की जाँच की अवधि में 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा जाँच अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध समझे जाने वाले आयातकों तथा घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित विधि और पद्धति से संगत सूचना निम्नलिखित पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकें और अपने विचारों से अवगत करा सकें :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिर्देशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

कमरा सं० 240, उद्योग भवन,

नई दिल्ली-110107

18. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जाँचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं को और प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों, जो पाटन, क्षति एवं नुकसान के संबंध में इस जाँच से संबंधित सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, को अवसर प्रदान किया जा रहा है। अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी जाँच संबंधी अपना अनुरोध निम्नलिखित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से कर सकता है।

समय-सीमा

19. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व पहुँच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें सम्बोधित पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय-सीमा के विस्तार के संबंध में प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. नियम 6(7) के अनुसार इच्छुक पार्टियों के लिए प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाली पार्टी की राय में ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो उसके कारण दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक सार्वजनिक फाइल रखी जाती है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

3223 GI/09-2

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2009

Sub. : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Acetone originating in or exported from Japan and Thailand.

No. 14/31/2009-DGAD.— Whereas Hindustan Organic Chemicals Ltd. (herein after referred to as applicant) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), alleging dumping of Acetone (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from Japan and Thailand, (hereinafter referred to as "subject countries") and requested for initiation of Anti-Dumping investigations for levy of anti dumping duties on the subject goods. The request is supported by M/S S I Group-India Ltd.

2. AND WHEREAS, the Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject Countries and injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

3. The product under consideration for the investigation is Acetone. The product is marketed in two grades Crystalline and Hydrated. The two grades are differentiated on the basis of flow characteristics of Acetone. Acetone is a basic organic chemical, which is also known as Dimethyl Ketone with a chemical formula CH_3COCH_3 . The product is manufactured through different processes such as Cumene route, Isopropyl Alcohol (IPA) based route and Ethanol Alcohol based route. Acetone is used in numerous organic synthesis either as a solvent or as an intermediate. It is used in the manufacture of bulk pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is used in the manufacture of Isophorone, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bisphenol-A. Besides this, Acetone is used in the manufacture of certain Rubber Chemicals, Oxy Acetylene, Cellulose Acetate and also as a solvent in the manufacture of Paints/Coatings.

4. Acetone is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under Tariff Heading No. 2914.11. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the present investigation.

Domestic Industry and Standing

5. The application has been filed by M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited and supported by M/S S I Group-India Ltd. There are only two known producers of the subject goods in the Country. According to the information provided in the application, the production of Hindustan Organic Chemicals Limited constitute 58% of Indian production during Apr'08-Sept'08 and 55% during Oct'08-Mar'09 and along with the supporter, it constitutes 100% of the Indian Production. Thus, the applicant shall constitute "domestic industry" for the purpose of the present investigations.

6. The Authority, after examining the above, determines that the applicant constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

Countries Involved

7. The countries involved in the present investigation are Thailand and Japan.

Like Article

8. Applicant has claimed that there is no significant difference in Acetone produced by the domestic industry and Acetone exported from subject countries. Both products are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Both the products are technically and commercially substitutable and hold closely resembling characteristics. It is further claimed that the consumers have used the two interchangeably. Therefore, for the purpose of present investigation, subject goods produced by the applicant are being treated as "Domestic Like Article" to the subject goods imported from subject countries within the meaning of the Anti Dumping Rules.

Normal Value

9. In the absence of availability of data in respect of the domestic sales in Thailand and Japan, the applicant has constructed normal value on the basis of constructed cost of production of subject goods in subject countries. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicant, subject to adjustments in the higher interest cost claimed in respect of Thailand, and the same has been considered by the Authority for the purpose of initiation.

Export Price

10. The export price of the subject goods from the subject Countries has been claimed on the basis of data obtained from International Business Information Services (IBIS), Mumbai. Price Adjustments have been claimed on account of Ocean Freight, Marine Insurance, Port Expenses and Inland Freight etc. and scaling down the same to reasonable limits normally adopted by the Authority. There is sufficient evidence of export prices claimed by the applicant for the subject goods from the subject countries.

Dumping Margin

11. Normal value and export price have been compared at ex-factory level in respect of the subject countries. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in Thailand and Japan, so arrived is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by exporters from subject countries into the Indian market.

Injury and Causal Link

12. The applicant has claimed that injury to the domestic industry has not been caused due to the factors other than the dumped imports, as shown below:

i. The subject goods are being imported primarily from Japan, Thailand and the countries already attracting duty. The imports from other countries are minimal.

ii. While demand has declined marginally during the POI in comparison to immediate previous year, subject imports during the same period have increased significantly in absolute terms and in relation to demand and production.

iii. The pattern of consumption with regard to PUC has not undergone any change and therefore could not have contributed to the injury.

iv. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

v. Technology for production of subject goods has not undergone any change and therefore, not a factor of injury.

vi. The applicant does not have significant export activities for the product concerned. The export performance of the applicant therefore, has not caused any injury to the domestic industry.

13. Once it is shown that there is an adverse volume and price effect from dumped imports, and the effects of injury caused by dumped imports then, the

only basis on which to conclude that the injury is not caused by the dumped imports is through non-attribution analysis, i.e., that other factors have caused the injury. As listed known other factors do not establish that injury has been caused by these other factors, the only inescapable conclusion is that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from a number of sources including subject countries. While the above parameters establish that injury to the domestic industry has not been caused by the other factors, applicant has submitted that the following parameters establish that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports.

- a) Imports from the subject countries were undercutting the prices of the domestic industry. As a direct consequence, the volume of imports increased significantly.
- b) Increase in the volume of dumped imports resulted in decline in sale volumes of the domestic industry.
- c) Decline in the sales volumes of the domestic industry resulted in decline in the market share of the domestic industry.
- d) Decline in prices of the domestic industry resulted in deterioration in profits, and consequently cash flow and return on capital employed for the domestic industry.

14. There is sufficient evidence that the dumped imports of subject goods from subject countries are, prima facie, causing material injury to the domestic industry.

Initiation of Antidumping Investigation

15. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject Countries.

Period Of Investigation

16. The Period of Investigation(POI) for the purpose of the present investigation is 1st October 2008 to 30th June 2009 (9 months). The injury investigation period will, however, cover the period 2006-07, 2007-08, 2008-09 and the POI.

Submission of Information

17. The known exporters in the subject Countries, their Governments through the Embassies, the importers in India known to be concerned with this investigation and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

3223 GI/09-3

**The Designated Authority
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi – 110107.**

18. As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation and to representative consumer organizations, who can furnish information relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

Time Limit

19 Information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

Submission of Information

20. In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Inspection of Public File

21. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by interested parties.

R. GOPALAN, Designated Authority